>

Title: The Minister of State in the Ministry of Agricutlure and the Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries laid a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): अध्यक्ष महोदया, शरद पवार जी की ओर से, मैं माननीय अध्यक्षा लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में कृषि से संबंधित स्थायी समिति की छियालिसवीं रिपोर्ट (2013-14) में शामिल की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

कृषि से संबंधित स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की छियालिसवीं रिपोर्ट 23.04.2013 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट वर्ष 2013-14 हेतु कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है और इसमें 14 सिफारिशें शामिल हैं। ये सिफारिशें मुख्यतया संकेन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों, कृषि क्षेत्र में विकास, मुक्त व्यापार समझौते, मूल्य समर्थन तंत्र, ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान निधियों के आबंटन व उपयोग, 12वीं योजना के दस्तावेज, 12वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान वित्तीय आबंटन एवं उपयोग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम, मक्का स्कीम के अंतर्गत तिलहन उत्पादन, विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना, केन्द्रीय योजना आबंटन आदि से पूर्वोत्तर राज्यों के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र व बजटीय आबंटन से संबंधित है। समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/प्रेक्षणों पर की गई कार्रवाई की विवरणी दिनांक 16.07.2013 को कृषि से संबंधित स्थायी समिति को भेजी गई थी।

समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का उल्लेख मेरे वक्तव्य के अनुबंध में किया गया है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं इस अनुबंध की विषय-वस्तु को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा, इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

...(*Interruptions*)